मुंबई(महाराष्ट्र) से प्रकाशित

हिन्दी दैनिक

उत्तरशक्ति

हर खबर निष्पक्षता के साथ

मुंबई
वर्षः 7 अंक 135
गुरुवार, 28 नवम्बर 2024
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshakti.co.in

अदाणी और संभल मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा, लोकसभा-राज्यसभा कल तक स्थगित

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। विपक्षी सांसदों के लगातार विरोध के बीच, लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया और गुरुवार, 28 नवंबर को फिर से बैठक होगी। वहीं, विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण संसद के उच्च सदन की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नारेबाजी के साथ शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने अडानी रिश्वत मामले और संभल हिंसा को लेकर हंगामा किया। संसद का शीतकालीन सत्र 2024 सोमवार, 25 नवंबर को शुरू हुआ, जिसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में अपना पारंपरिक संबोधन दिया, जिसमें सभी सांसदों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक चर्चा में शामिल होने का आग्रह किया गया।

विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक बुधवार को एक बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने के साथ ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठाने का प्रयास करने लगे, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने संभल की घटना को उठाने का प्रयास किया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच प्रश्नकाल शुरू कराया।

इस बीच, कांग्रेस और सपा के कई सदस्य आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की।

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अरुण गोविल का उल्लेख करते हुए कहा कि वह पहली बार प्रश्नकाल में प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसे में सदन की कार्यवाही चलने दी जाए। हालांकि, हंगामा नहीं थमा और विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। दोपहर 12 बजे निचले सदन की बैठक फिर शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए।

विपक्षी सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। हालांकि, शोर-शराबे के कारण सदन की बैठक दिनभर के स्थगित कर दी गई।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानूनों के बारे में बात की।

अमित शाह करेंगे महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर फैसला, नई दिल्ली में महायुति की बैठक कल

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महायुति गठबंधन गुरुवार को अगली महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि तीन सहयोगी दल शिवसेना शिंदे, राकांपा अजित पवार और भाजपा- इस मामले पर चर्चा के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। कार्यवाहक सीएम ने ठाणे में अपने घर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी, शिवसेना उसका समर्थन करती है, कल हम दिल्ली में अमित शाह के साथ सरकार

गठन पर फैसला करेंगे। कई दिनों के राजनीतिक सस्पेंस के बाद, एकनाथ शिंदे ने बुधवार को देवेंद्र फडणवीस के लिए राज्य का अगला नेता बनने का रास्ता साफ कर दिया। महाराष्ट्र भाजपा द्वारा देवेन्द्र फडणवीस पर जोर देने के बावजूद, गठबंधन ने सीएम चयन पर औपचारिक घोषणा में देरी की है, गठबंधन सद्भाव बनाए रखने के लिए शिंदे को शामिल करने की मांग की है। इस बीच शिंदे ने राज्यपाल सी.पी. से मुलाकात की। राधाकृष्णन ने मंगलवार सुबह राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने अनुरोध किया कि शिंदे नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका में बने रहें। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर कई दिनों से चल रहे सस्पेंस को खत्म करते हुए कार्यवाहक-सीएम एकनाथ शिंदे ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और खुद को सीएम की दौड़ से बाहर कर दिया। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय हो गया है। उन्होंने प्रचंड जीत के लिए राज्य की

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कार और ट्रक में भिड़ंत, 5 डॉक्टरों समेत छह की मौत

कन्नौज, 27 नवम्बर। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दुखद घटना में कार और ट्रक में टक्कर होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से जा टकराई। जानकारी के अनुसार, मरने वाले छह लोगों में से पांच पेशे से डॉक्टर थे। पीड़ित सैफई मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे और लखनऊ से सैफई लौट रहे थे। यह हादसा तिर्वा कोतवाली क्षेत्र में 196 किलोमीटर के पास हुआ। अधिकारी दुर्घटना के सही कारण का पता लगाने के लिए घटना की जांच कर रहे हैं। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 3:43 बजे

हुआ। कथित तौर पर चालक को झपकी आने के बाद कार ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर तोड़कर विपरीत दिशा में जा रहे ट्रक से जा टकराई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में पांच डॉक्टरों समेत छह लोगों की मौत हो गई। जयवीर सिंह नामक एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसका सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है और शवों को शवगृह भेज दिया गया है।

अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही हैः राहुल गांधी

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज निलंबित कर दिए गए।

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा

कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लिखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है, वह आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए। सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा। इसलिए वे स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। मूल मुद्दा यह है कि ये अभियोग भारत के कारोबारी माहौल के संबंध में किस तरह का संदेश भेजते हैं। उन्होंने कहा कि नंबर दो, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या कर रहा था? यदि अमेरिकी नियामक को अभियोग दायर करने के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं। यदि आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को याद करें, तो अडानी समूह के संबंध में मुद्दे न केवल सार्वजनिक डोमेन में थे, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी इस पर आंदोलन किया जा रहा था या फैसला सुनाया जा रहा था। तो सवाल यह है कि नियामकों को विनियमित कौन करेगा? इसलिए, इसमें बड़े मुद्दे शामिल हैं।

और इसीलिए हम संसद के दोनों सदनों में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

संभल हिंसा में पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन में योगी सरकार, होगी नुकसान की वसूली

संभल। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि संभल हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भुगतान करना होगा और पत्थरबाजों के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। संभल में रविवार (24 नवंबर) को कोट गर्वी इलाके में शहर की शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर किए गए सर्वेक्षण पर टकराव के बाद चार लोगों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों सहित कई घायल हो गए, एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया कि एक बार हरिहर मंदिर था साइट पर खड़ा था। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि संभल हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ यूपी सरकार सख्त रुख अपना रही है। पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाए जाएंगे और नुकसान की भरपाई की मांग की जाएगी। उनकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को इनाम की भी घोषणा की जा सकती है। इसी तरह की पहल में, सरकार ने पहले 2020 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान बर्बरता से जुड़े व्यक्तियों के पोस्टर लगाए थे। ये पोस्टर राज्य की राजधानी सहित कई स्थानों पर प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन बाद में अदालत के आदेश के बाद हटा दिए गए थे। संभल पुलिस ने मोबाइल सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों का उपयोग करके हालिया हिंसा के दौरान पथराव में शामिल 100 से अधिक लोगों की पहचान की है। इनमें से कुछ नाबालिगों समेत 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चौंकाने वाले खुलासे में, पुलिस ने पाया कि कुछ पत्थरबाजों ने खुद को आंसू गैस के प्रभाव से बचाने के लिए अपनी आंखों के चारों ओर हरा लोशन का इस्तेमाल किया था।

उच्चतम न्यायालय ने यमुना एक्सप्रेसवे के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण को रखा बरकरार

नई दिल्ली, 27 नवम्बर। उच्चतम न्यायालय ने एक अहम फैसले के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की वैधता को मंगलवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने जमीन मालिकों और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (वाईईआईडीए) की ओर से दायर अपील और ह्यक्रॉस-अपीलह्ल पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया। ये मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो विरोधाभासी फैसलों से उपजे थे। एक फैसले में वाईईआईडीए की ओर से भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा गया था, जबकि दूसरे फैसले में अति आवश्वयक धाराओं को लागू करते हुए

किसानों की जमीन अधिग्रहीत करने की राज्य सरकार की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने जमीन मालिकों की याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि वाईईआईडीए की ओर से दाखिल अर्जियों को स्वीकार कर लिया। इसी के साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 के अति आवश्यक प्रावधानों को लागू करने पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो गया।

न्यायमूर्ति मेहता ने पीठ के लिए 49 पन्नों का फैसला लिखते हुए कहा कि अधिग्रहण को यमुना एक्सप्रेसवे के विकास के लिए अहम माना गया है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि एक्सप्रेसवे का निर्माण और आसपास के क्षेत्रों का विकास सार्वजनिक-हित की एक एकीकृत परियोजना के दो अविभाज्य घटक हैं।

इसमें कानून के अति आवश्यक प्रावधानों को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा गया है और कहा गया है कि यह क्षेत्र की विकास नीति के तहत उचित था। फैसले में कहा गया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के बारे में चिंता और तेजी से विकास की आवश्यकता के कारण संबंधित कानून के तहत सामान्य जांच को दरकिनार करना जरूरी है।

पीठ ने कहा कि प्रभावित जमीन मालिकों में से अधिकांश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से निर्धारित मुआवजे को स्वीकार कर लिया है और नो लिटिगेशन बोनस के रूप में दिए जाने वाले 64.7 फीसदी बढ़े हुए मुआवजे का समर्थन किया है।

पीठ ने सभी प्रभावित पक्षों के लिए लाभ में एकरूपता बनाए रखने पर जोर देते हुए मुआवजा राशि में और वृद्धि करने से इनकार कर दिया।

"स्वच्छ जल से ही स्वस्थ जीवन"
सस्ते एवं उचित दर पर, आपकी सेवा में समर्पित, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें
पुर्णिमा सर्विसेस
COMPLETE SOLUTIONS OF WATER TREATMENT
ALL TYPES WATER PURIFIER SERVICE
Email - purnima.services@gmail.com
8655185584
Shop No. 7, Gr. Floor , Prerna Tower, Diva - Shil Road , Diva (E) - 400612

THE DOCTORS COACHING
अब आपके विकास नगर लखनऊ में
Your Gateway to Success in NEET & Foundation Exams!
Powered by- Modern Kids Education Pvt.Ltd. (Since 1999)
NEET (UG) & FOUNDATION
Director Dr. Abid Khan PhD (USA)
Physics Chemistry Biology
9th, 10th, 11th & 12th
Smart Classes
Fully Air- Conditioned Classes
The Doctors Coaching Your Gateway to success in NEET a foundation exams!
ADMISSION OPEN NOW!
www.thedoctorcoaching.com | edu@thedoctorcoaching.com
+91- 7080403322, +91- 8400043322
Near LHPS, Friends Colony, Sector- 7, Vikas Nagar, Lucknow- 226022

जलवायु परिवर्तन के खतरों से बच्चों को बचाएं

-ललित गर्ग

हाल ही में प्रस्तुत हुई यूनिसेफ की रिपोर्ट ह्यद फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रेन इन चेंजिंग वर्ल्डह्ल ने भारत में बच्चों के भविष्य को लेकर उत्पन्न चुनौतियों, त्रासद स्थितियों एवं भयावह भविष्य को उजागर किया है। इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि साल 2050 तक भारत में 35 करोड़ बच्चे जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु संकट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी बदलावों की चुनौतियों का सामना कर रहे होंगे। उस समय जन्म लेने वाले बच्चों को जन्म के बाद जीवन में जलवायु परिवर्तन के संकटों से जुझना होगा, भीषण लू, गरमी, बाढ़, तूफान, चक्रावात और अनेक जलवायु जनित बीमारियों से सामना करना होगा। वायु प्रदूषण की विभीषिका, गहराते जल संकट, सिमटते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन व रोजगार की विसंगतियों के बीच आने वाली पीढ़ी के बच्चों का जीवन निस्संदेह संघर्षपूर्ण, चुनौतीपूर्ण एवं संकटपूर्ण होगा। वर्ष 2021 में बच्चों के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत कुल 163 देशों की सूची में 26वें स्थान पर था। ऐसे में भारत में बच्चों को अधिक गर्मी, बाढ़ और वायु प्रदूषण से गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। खासकर ग्रामीण और कम आय वाले समुदायों में यह संख्या ज्यादा है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि 2050 में बच्चों को 2000 के दशक की तुलना में लगभग आठ गुना ज्यादा गर्मी झेलनी पड़ सकती है। जाहिर है, जलवायु संकट बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा तथा पानी जैसे आवश्यक संसाधनों तक उनकी पहुंच पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। चिंता की बात यह है कि इन तमाम विसंगतियों, विषमताओं व नेतृत्व की अदूरदर्शिता के बीच बच्चों के भविष्य पर मंडरा रहे खतरों के लिये संवेदनशीलता के साथ सावधान एवं सतर्क होने एवं उचित-प्रभावी कार्ययोजना बनाने की जरूरत है।

इसी तरह, गहरे डिजिटल विभाजन के बीच एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बच्चों के लिए अच्छी और बुरी, दोनों हो सकती है। एक ताजा आंकड़ा बताता है कि उच्च आय वाले देशों में 95 फीसदी आबादी इंटरनेट से जुड़ी है, तो निम्न आय वाले देशों में सिर्फ 26 प्रतिशत लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है। भारत में वर्तमान में इंटरनेट की व्यापकता ने बच्चों के जीवन में अनेक संकट खड़े किये हैं। यूनिसेफ ने इस डिजिटल डिवाइड को पाटने और बच्चों तक नयी प्रौद्योगिकियों की सुरक्षित एवं समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशी प्रौद्योगिकी पहल की वकालत की है। बच्चे चूंकि हमारा भविष्य हैं, इसलिए बच्चों और उनके अधिकारों को सरकारी नीतियों-रणनीतियों के केंद्र में रखना समृद्ध और टिकाऊ भविष्य के निर्माण एवं संतुलित-आदर्श समाज-व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अक्सर यह सवाल विमर्श में होता है कि धरती के प्रति गैर-जिम्मेदार व्यवहार के चलते हम कैसा देश आने वाली पीढ़ियों के लिये छोड़कर जाएंगे। आने वाले पच्चीस वर्षों में बच्चों पर लू का 8 गुणा, बाढ़ का 3 गुणा एवं जंगली आग का दोगुणा खतरा होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने बच्चों के भविष्य की तस्वीर उकेरते हुए विभिन्न चुनौतियों के मुकाबले के अनुरूप नीति निर्माण की जरूरत बतायी है। यूनिसेफ ने सदी के पांचवें दशक तक की तीन महत्वपूर्ण वैश्विक प्रवृत्तियों का खाका खींचा है। ये घटक नौनिहालों के भविष्य के जीवन को नया स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाएंगे।

वर्ष 2050 तक देश की आधी आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने का अनुमान है। दरअसल, मौजूदा दौर में जिस तेजी से गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है, जाहिर है ऐसी स्थिति में पहले से आबादी के बोझ तले दबी नागरिक सेवाएं चरमरा जाएंगी। ऐसे में सत्ताधीशों के लिये जरूरी होगा कि जलवायु परिवर्तन के संकट के बीच बच्चों के अनुरूप शहरी नियोजन को अपनी प्राथमिकता बनाएं और बच्चों के अनुकूल और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से जुझारु, सुरक्षित एवं निरापद शहरी नियोजन के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और टिकाऊ शहरी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी जाये। शहर बेहतर जीवन के लिए बेहतरीन अवसर और उम्मीद दे सकते हैं। वे वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करते हैं और उन्हें तेजी से विकास हासिल करने के लिए इंजन माना जाता है। वे विकास और नवाचार, विविधता और कनेक्टिविटी के दुनिया के सबसे मजबूत स्त्रोतों में से हैं और संभावित रूप से बच्चों को जीने, सीखने और आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान कर सकते हैं।

बढ़ता शहरीकरण बड़ी असमानताओं को भी जन्म दे सकते हैं। आज शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 4 बिलियन लोगों में से लगभग एक तिहाई बच्चे हैं। यह अनुमान है कि 2050 तक, दुनिया के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जिनमें से कई झुग्गी-झोपड़ियों में रहेंगे। इसलिये शहर स्कूलों और अस्पतालों जैसी बुनियादी सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान कर सकते हैं, भीड़भाड़ और उच्च प्रवेश लागत के कारण सबसे गरीब शहरी बच्चे उन तक पहुंचने में असमर्थ हो सकते हैं। अन्य चुनौतियाँ जो शहरी गरीबों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को, उनमें भीड़भाड़ और अपर्याप्त सफाई व्यवस्थाएं शामिल हैं-जो बीमारियों के फैलने में सहायक होती हैं-किफायती और सुरक्षित आवास की कमी, परिवहन की खराब पहुंच और बाहरी वायु प्रदूषण में वृद्धि आदि हैं। उल्लेखनीय है कि उस समय देश जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौती से जूझ रहा होगा। आकलन किया जा रहा है कि इस बदलाव के चलते ही वर्तमान की तुलना में बच्चों की संख्या में करीब दस करोड़ की कमी आएगी। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक अरब बच्चे उच्च जोखिम वाले जलवायु खतरों का मुकाबला कर रहे हैं, तो अगर सरकारें अभी से नहीं चेती तो 2050 की स्थिति का सहज आकलन किया जा सकता है। मासूम चेहरों एवं चमकती आंखों का नया बचपन भारत के भाल पर उजागर एवं कायम करने के लिये सरकारों को गंभीर होना होगा।

बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान आधुनिक मानवतावाद और पूंजीवाद से प्रभावित होकर प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इससे परिवारों और बाल देखभाल प्रदाताओं पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। वर्तमान में मौजूद रहने के बजाय, लोग भविष्य के बारे में सोचने में अधिक से अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। और ज्यादातर मामलों में ये इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि व्यापक अर्थों में सफल जीवन कैसा हो सकता है, बल्कि इसके बजाय वे स्कूल और कार्यस्थल में सफलता के बारे में सोच रहे हैं। यह कुछ कौशलों पर बहुत अधिक जोर देता है, जबकि अन्य-जैसे रचनात्मकता, सामाजिक क्षमता, जीवनमूल्य और उत्साह-को कम महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे अधिक उन्नत शैक्षणिक ट्रैक या अधिक प्रतिष्ठित करियर में चयन के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चों में कई प्रतिभाएँ अविकसित रह जाती हैं। अगर समस्या को भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है-चाहे वह भविष्य आखिरकार कैसा भी क्यों न हो, तो भविष्य के खतरों की आहट को सुनते हुए जागरूक होना होगा। साफ है, नीति के स्तर पर प्रदूषण एवं बदलते मौसम की मार के लिये काम करना होगा। कम से कम भविष्य या बच्चों के लिये तो ऐसा किया ही जाना चाहिए।

निश्चित ही यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट बच्चों के भविष्य की चिंताओं पर मंथन करने तथा उसके अनुरूप नीति-नियंताओं से नीतियां बनाने का सबल आग्रह करती है। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में डिजिटल विभाजन भी एक बड़ी चुनौती होगी। तब तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग चरम पर होगा। जाहिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता जहां तरक्की का मुख्य साधन होगी, वहीं इसकी विसंगतियों का प्रभाव रोजगार के अवसरों एवं सामाजिक-पारिवारिक संरचना पर भी पड़ेगा। जहां दुनिया के विकसित देशों में अधिकांश आबादी इंटरनेट से जुड़ने के कारण प्रगति की राह में सरपट दौड़ रही है, तो गरीब मुल्कों में यह प्रतिशत विकसित देशों के मुकाबले करीब एक चौथाई ही है। ऐसे में समतामूलक आदर्श समाज की स्थापना के लिये डिजिटल डिवाइड को खत्म करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके मद्देनजर हमारी कोशिश हो कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का स्वरूप समावेशी हो। ताकि आधुनिक तकनीक तक बच्चों की समान व सुरक्षित पहुंच हो सके। निर्विवाद रूप से बच्चे आने वाले कल के ऐसे देश का भविष्य निर्धारक होते हैं। ऐसे में हर लोक कल्याणकारी सरकार का नैतिक दायित्व है कि अपनी रीतियों-नीतियों में बच्चों के हितों व अधिकारों को प्राथमिकता दे। तभी हम उनके सुखद भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं।

दुनिया के सबसे शर्मनाक अपराधों में से एक है मानव तस्करी समस्या

अशोक भाटिया

मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है और दुनिया के सबसे शर्मनाक अपराधों में से एक है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है और उनकी गरिमा को छीनता है। तस्कर दुनिया के सभी कोनों से महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को धोखा देते हैं और उन्हें हर दिन शोषणकारी परिस्थितियों में धकेलते हैं। जबकि मानव तस्करी का सबसे प्रसिद्ध रूप यौन शोषण के उद्देश्य से है, सैकड़ों हजारों पीड़ितों को जबरन श्रम, घरेलू दासता, बाल भीख मांगने या उनके अंगों को निकालने के उद्देश्य से तस्करी की जाती है।मानव तस्कर लोगों को वस्तु मानते हैं; ऐसी वस्तुएँ जिनका शोषण किया जा सकता है और लाभ के लिए उनका व्यापार किया जा सकता है। यूरोप में, अधिकांश दोषी तस्कर पुरुष हैं, हालाँकि अन्य अपराधों की तुलना में महिला अपराधियों का प्रतिनिधित्व अधिक है, क्योंकि कुछ गिरोह महिलाओं को पीड़ितों का विश्वास जीतकर उन्हें फँसाने में अधिक प्रभावी मानते हैं।

हाल ही में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (सीबीआई) ने भारत में मानव तस्करी से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह नौकरी दिलाने के नाम पर भारतीयों को रूस-यूक्रेन युद्ध के क्षेत्र में ले जाते थे। जिसके बाद उन्हें रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। सीबीआई ने इस मामले को लेकर सात शहरों के 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया था।

जानकारी के अनुसार सीबीआई ने कई वीजा परामर्श फर्मों और एजेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसी ने सात शहरों में 10 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तलाशी की। यह कार्रवाई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, अंबाला और मदुरई में की गई है। पुछताछ के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही एजेंसी ने 50 लाख रुपए सहित कई दस्तावेज, लैपटाप, मोबाइल, डेस्कटाप आदि इलेक्ट्रानिक रिकार्ड भी जब्त किए। जानकारी के लिए बता दें कि आकर्षक नौकरियों देने की आड़ में यह लोग बेरोजगार युवकों को झांसा देकर रूस-यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में भेजते थे। इस आरोप में सीबीआई ने कई वीजा कंसल्टेंसी फर्मों और एजेंट्स के खिलाफ मामला दर्ज किया।

बता दें कि एजेंसी की जांच में अब तक 35 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भारतीयों को अच्छी नौकरियों का झांसा देकर विदेश भेजा गया है। इसके साथ अब तक दो ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां रूस की सेना की ओर से लड़ते हुए भारतीयों की मौत हो गई है। उन दोनों को भी नौकरा का झांसा देकर ही रूस ले जाया गया था। नौकरी का झांसे देकर इन लोगों को विदेश लेजाने के बाद जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि अब तक विदेश भेजे गए युवकों में से कितनों को जंग में लड़ने को तैनात किया गया है, इसका आंकड़ा साफ नहीं हो पाया है। यह एजेंट्स न सिर्फ युवकों को झांसा देकर विदेश लेकर जाते थे, बल्कि उनसे पैसे भी लेते थे।

ऐसी मानव तस्करी को रोकने के लिए सरकार के साथ झ साथ समाज को भी चेतना होगा । सबसे पहले देश के नौजवानों और उनके माता-पिताओं को सावधान रहना होगा । सोशल मीडिया यू-ट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई नौकरी का ऑफर देता है, स्टूडेंट वीजा पर विदेश भेजकर वहां हर महीने लाखों रूपए कमाने का लालच देता है, तो बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, वरना पैसा भी जाएगा और जान जाने की नौबत भी आ सकती है क्योंकि इसी तरह के वीडियो के चक्कर में फंस कर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों के लड़के रूस पहुंच गए।

सनद रहे कि ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स और वीजा दिलाने के नाम पर लोगों को फंसाने का मानव तस्करी का ये नेटवर्क बड़े सुनियोजित तरीके से काम करता है। प्राइवेट वीजा कंसल्टेंसी की अलग अलग कपनियां सोशल मीडिया पर वीडियो, और यू-ट्यूब के जरिए, उन युवाओं से कनेक्ट होते थे जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, फिर इन नौजवानों को बताया जाता था कि विदेश में उनके लिए नौकरियों के तरह तरह के ऑप्शन हैं। जैसे डिलीवरी बॉय, हेल्पर, डेटा ऑपरेटर वगैरह। रूस के बारे में ये एजेंट दावा किया जाता है कि युवकों को वहां जाकर बॉर्डर पर जाकर न टैंक चलाना है, न तोप के गोले दागने हैं, इन कंपनियों के एजेंट रूस में भी मौजूद हैं। वो वहां से वीडियो बनाकर दिखाते थे कि रूस में हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, सेना मोर्चे पर है, लेकिन सिविलियन इलाकों में लाइफ नॉर्मल है और उनको सिविलियन इलाकों में काम करना है। ये एजेंट दावा करते थे कि ये सब काम करने के लिए युवकों को तीन महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और पहले तीन महीने तक हर महीने 40 हजार रुपए सैलरी भी मिलेगी। तीन महीने की ट्रेनिंग के बाद जब इन युवकों की पोस्टिंग होगी, तो उनकी सैलरी बढ़कर एक लाख रुपए प्रति महीना हो जाएगी। विदेश में बसने का सपना देख रहे पढ़े-लिखे नौजवान उनके झांसे में आ जाते थे और वो रूस जाने के लिए जैसे तैसे तीन लाख रुपए इकट्ठा करते थे लेकिन, जैसे ही ये युवक रूस पहुंचते थे, इन एजेंटों का असली खेल शुरू हो जाता था। उनसे रूसी भाषा में एक कॉन्ट्रैक्ट पर जबरन साइन कराया जाता था और बंदूक, राइफल चलाने की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर जंग के मोर्चे पर भेज दिया जाता था। जो लोग इसका विरोध करते थे, उनको 10 साल के लिए जेल में डालने की धमकी दी जाती थी।

इस पूरे रैकेट में सबसे ज्यादा चर्चा बाबा व्लॉग्स नाम के एक एजेंट की हो रही है। ये असल में दुबई में रहने वाले फैसल अब्दुल मुतालिब खान का वीडियो ब्लॉग है। सबसे ज्यादा नौजवान इसी फैसल अब्दुल मुतालिब खान के वीडियो देखकर एजेंट्स के जाल में फंसे। इस बाबा व्लॉग के कई वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। ये फैसल अब्दुल मुतालिब खान दुबई की एक कंपनी में डायरेक्टर है। इस कंपनी का नाम बाबा व्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ये शख़्स रूस के अलग अलग शहरों से अपने वीडियो डालकर लोगों को यकीन दिलाता था कि रूस में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे में नौजवानों को वहां आकर नौकरी करने में कोई रिस्क नहीं है। इस ब्लॉगर ने दो दर्जन लड़कों को रूस भेजा लेकन जब रूस यूक्रेन की जंग में दो भारतीय नौजवानों की मौत की खबर आई तो हमारी सरकार और एजेंसीज एलर्ट मोड में आईं। धोखाधड़ी की ऐसी ही घटनाओं पर एक्शन लिया। सीबीआई ने इस तरह की 17 प्लेसमेंट एजेंसीज का पता लगाया। दिल्ली, मुंबई, अंबाला चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नै समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने 17 कंपनियों और उनके मालिकों पर केस दर्ज किया। दिल्ली में ओवरसीज फाउंडेशन और इसके निदेशक सुयश मुकुट के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ओवरसीज फाउंडेशन के ठिकानों पर रेड्स भी हुई हैं। ओवरसीज फाउंडेशन का ऑफि स दिल्ली में कस्तूरबा गांधी रोड पर अंबादीप बिल्डिंग में है। इसी तरह, सीबीआई ने मुंबई की ओएसडी ब्रदर्स ट्रैवल्स ऐंड वीजा सर्विसेज और इसके निदेशक राकेश पांडेय पर केस रजिस्टर किया। इसके ठिकानों पर रेड की, हालांकि राकेश पांडेय गिरफ़्त में नहीं आया। चंडीगढ़ और अंबाला की एडवेंचर वीजा सर्विसेज और इसके डायरेक्टर मंजीत सिंह के खिलाफ भी एक्शन हुआ। सीबीआई ने दुबई की बाबा व्लॉग्स ओवरसीज रिक्रूटमेंट सॉल्यूशंस और इसके निदेशक फैसल अब्दुल मुतालिब खान उर्फ. बाबा के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। सीबीआई के मुताबिक, जबरन प्राइवेट आर्मी में भर्ती करने के कम से कम 35 मामले सामने आए हैं, अब सबकी जांच की जा रही है। सीबीआई की रेड में 50 लाख नकद और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कुछ वीडियो भी मिले हैं। बाबा व्लॉग के झांसे में आकर रूस गए हैदराबाद के एक युवक मुहम्मद आफशान की जंग लड़ते हुए मौत हो गई। उसे वापस भारत लाने के लिए अफशान के भाई ने हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी से गुहार लगाई। ओवैसी ने विदेश मंत्रालय के साथ ये मसला उठाया। पिछले हफ़्ते अफशान के परिवार को उसकी मौत की खबर मिली। अफशान के भाई मुहम्मद इमरान अब अपने भाई की लाश वापस लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सूरत के हेमिल मांगुकिया भी अफशान की तरह मानव तस्करी करने वालों के चक्कर में फंसकर रूस गए थे। 21 फरवरी को यूक्रेन के एक ड्रोन हमले में हेमिल की मौत हो गई। भारत सरकार की कोशिशों का एक असर ये हुआ है कि रूस की सरकार ने मोर्चे पर फंसे भारतीयों को बॉर्डर से हटाना शुरू कर दिया है, उन्हें सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है लेकिन मुश्किल ये है कि जो भारतीय नौजवान रूस और यूक्रेन की जंग में फंस गए हैं, उन्हें जंग के मैदान में भेजने में न तो भारत सरकार की और न ही रूसी सरकार की कोई भूमिका है। ये लोग प्राइवेट एजेंट्स के चक्कर में फंसे और उन्हें प्राइवेट रशियन सशस्त्र ग्रुप के हवाले कर दिया जिनका रूसी सेना से कोई लेना देना नहीं। ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं।

इसलिए सरकार व समाज को पहले इन भारतीयों की पहले पहचान करनी पड़ेगी उनके ठिकानों का पता लगाना होगा। उसके बाद उनको सुरक्षित जगहों पर लाकर उन्हें भारत लाने की कोशिश होगी। ये काम बहुत मुश्किल है, इसलिए इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए सरकार भी कह रही है और मैं भी अपील करूंगा कि विदेश जाने के चक्कर में प्राइवेट एजेंसियों और एजेंट्स के चक्कर में न फंसे। विदेश में बढ़िया सैलरी पर अच्छी नौकरी का कोई झांसा देता है तो उस पर यकीन न करें। बैकग्राउंड चैक करें। जिस देश में नौकरी की बात कही जा रही है। उसके दूतावास से संपर्क करें। सारे फैक्ट्स चैक करें। फिर अपने विदेश मंत्रालय के जरिए लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही विदेश जाएं। अगर टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा पर नौकरी का वादा करके विदेश भेजने की बात कहता है तो उस पर बिल्कुल यकीन न करें, क्योंकि इसमें पैसा भी जाएगा और जिंदगी भी खतरे में पड़ेगी। इसलिए सावधान रहें। सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो और रील्स पर कतई भरोसा न करें,वरना मुश्किल में पड़ना तय है।

अंत में खास बात यह है कि मानव तस्करी से लड़ना सिर्फ. अधिकारियों की ज़िम्मेदारी नहीं मानी जानी चाहिए। आम लोग इस अपराध से निपटने में मदद कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूक होकर और यह सुनिश्चित करके कि पीड़ितों की दुर्दशा अनदेखी न हो। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इस अपराध से निपटने में मदद कर सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं।

श्याम देव राय चौधरी दादा की हर सांस संघर्ष की दास्तान थी

-सुरेश गांधी

वाराणसी. सात बार विधायक एवं जनसेवा में जीवनपर्यंत समर्पित रहे भाजपा नेता श्याम देव राय चौधरी अब नहीं रहे। प्यार से लोग उन्हें ह्लदादाह्ल कहते थे। वे काशीवासियों के दिलों पर इस कदर राज करते थे इसकी बानगी उस वक्त लगी जब उनके निधन की खबर पल भर में ही जंगल में लगी आग की तरह फैल गयी और हर आंखे नम दिखी। जनसमस्याओं को लेकर अक्सर वे अनशन पर बैठ जाते थे, नौ दिन के अनशन पर सपा भी उनके सामने नतमस्तक हो गई थी। उनकी खासियत थी कि वह जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कराने में विश्वास रखते थे। पार्षद के तौर पर सियासी सफर की शुरूआत करने वाले दादा का हमेशा जमीन से जुड़े रहना सगल बन गया था। बेहद सादगी भरा जीवन जीने वाले दादा हमेशा रिक्शे से या फिर पैदल ही चलते नजर आते थे.

विधायक रहते हुए उन्होंने कभी भी ना ही सरकारी सुविधा का लाभ लिया और नहीं गाड़ियों का इस्तेमाल किया। अक्सर वे जाने आने के लिए राह चलते लोगों की मोटरसाइकिल पर बैठकर ही कहीं आया जाया करते थे. चाय और पान की दुकान पर इनसे अक्सर लोग मिलते थे. श्यामदेव राय चौधरी की छवि बेहद ही सादगी भरी मानी जाती रही. उनके निधन पर खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। बता दें,दादा वाराणसी के शहर दक्षिण से लगातार सात बार विधायक रहे। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने 26 नवंबर की सुबह अंतिम सांस ली। खास यह है कि जब तक वे जीएं उनकी हर सांस संघर्षो में बीता और जब अस्पताल के बेड पर पड़े तो वहां भी पखवारे भर जीवन-मृत्यु से संघर्ष में ही बीता। पिछले मंगलवार यानी 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनकी खैरियत पूछी थी और उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने वाराणसी दौरे के दौरान चौधरी को देखने अस्पताल गए थे.

कुछ समय के लिए मंत्री रहे दादा जनता में काफी लोकप्रिय थे और भाजपा के काशी क्षेत्र के बड़े चेहरे के रूप में उनकी पहचान थी। 2017 में उनकी उम्र को देखते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके पूर्व दादा कांग्रेस की गढ़ कही जाने वाली वाराणसी दक्षिणी पर लगातार सात बार जीत हासिल कर पार्टी का जनाधार तैयार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादा के निधन के बाद भाजपा हीं नहीं अन्य पार्टी के नेताओं में भी शोक की लहर दौड़ गई। उनके आवास पर विभिन्न पार्टियों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दादा को अंतिम सलामी दी गई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। बनारस के लोगों से उनका काफी जुड़ाव रहा। यही कारण है कि लोग उन्हें बड़े भाई की तर्ज पर दादा कहते थे। मिलनसार और व्यक्तित्व के धनी श्याम देव दादा विधायक का पद चले जाने के बाद भी लोगों की मुसीबत में खड़े रहते थे। उनका साथ देते थे। वे वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट पर 1889 से 2017 तक लगातार भाजपा पार्टी से विधायक रहे। इसके साथ ही भाजपा सरकार में श्याम देव दादा कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। 2007 और 2012 में प्रोटेम स्पीकर भी रहे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से पार्टी और जनता की सेवा की। 22 जून 1939 को जन्में श्याम देव राय चौधरी दादा बचपन से ही जुझारू प्रवृत्ति के थे। अपनी सादगी के कारण वे पूर्वांचल के लोकप्रिय नेता बने। वे मूलरूप से पूर्वी बंगाल के रहने वाले थे और अपने पिता के साथ काशी आए थे। अपनी विचारधारा को और विस्तारित करने के लिए वे संघ से जुड़ गए और निरंतर सक्रिय रहे। उम्र अधिक होने के चलते भाजपा ने 2017 विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं दिया था, इससे वे नाराज थे, उनकी नाराजगी को देखते हुए पीएम मोदी ने उनसे खास मुलाकात की थी। इसके बाद से वह राजनीति से ही संन्यास ले लिया। बावजूद इसके लोग उनके पास राजनीतिक सलाह लेने जाते थे। टिकट कटने के बावजूद दादा ने भाजपा के विरोध में कभी भी बयानबाजी नहीं की। उनके समर्थकों ने भी अपनी नाराजगी दिखाई थी। बनारस में 2017 की विधानसभा के लिए भाजपा ने जब अपना रोड शो किया तो श्याम देव राय चौधरी दादा भी इसमें शामिल रहे, लेकिन दूर-दूर थे। पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर के पास उनका हाथ पकड़ लिया और दोनों नेता साथ-साथ गभगृह जाकर बाबा का दर्शन-पूजन किए। उनकी खासियत यह थी कि वे शहर दक्षिणी के विधायक जरुर थे, लेकिन पूरे बनारस को अपना मानते थे। यही कारण था कि कहीं भी जनमस्या होने पर वे जनता के साथ खड़े दिखते थे। यही नहीं समस्या का समाधान न होने पर वे अनशन और भूख हड़ताल पर भी बैठ जाते थे। 2015 में शहर में हुए बिजली समस्याओं को लेकर उन्होंने एक बार लंबा अनशन किया। इसी दौरान तत्कालीन सपा सरकार से बिजली समस्याओं के निराकरण की त्वरित मांग की। उनकी जिद के आगे सपा शासन को झुकना पड़ा।

दादा समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारियों के आगे अड़ जाते थे। सरकारी विभागों के पास धरने पर बैठना... अनशन कर देना... उनके लिए आम बात थी। यही बात उन्हें जनता से जोड़ती भी थी। भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री का भी पद संभाल चुके, श्यामदेव राय चौधरी को 2007 और 2012 में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी नियुक्त किया गया था. मिलनसार और व्यक्तित्व के धनी श्याम देव दादा विधायक का पद चले जाने के बाद भी लोगों की मुसीबत में खड़े रहते थे। उनका साथ देते थे।

धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए मारकाट कब थमेगी?

-डॉ. सत्यवान सौरभ

संभल में दायर याचिका वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के शाही ईदगाह के लिए दायर याचिकाओं की तरह ही है। मुख्य मुद्दा यह है कि कानून-'पूजा स्थल अधिनियम, 1991' को कैसे समझा जाता है। संभल की ज़िला अदालत ने शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश एक याचिका के आधार पर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि यह हिंदू मंदिर स्थल पर बनी है। इस आदेश के कारण स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने इसे अपने धार्मिक अधिकारों और विरासत पर हमला माना। जब सर्वेक्षण का विरोध करने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। रिपोर्ट बताती हैं कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों दोनों को चोटें आईं और मौतें हुईं। भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।

संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की ओर से जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरि समेत 8 वादी हैं। वादियों ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद समिति को विवाद में पार्टी बनाया है। याचिका में कहा गया- 'मस्जिद मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदल दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था। बाबरनामा और आइन-ए-अकबरी किताब में इस बात का उल्लेख है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है, वहाँ कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।' मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वह अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के समय भी इस पर जोर दिया था। इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक जताता है और हिंदू पक्ष के दावे, किसी अन्य न्यायिक कार्यवाही को कानून की अवहेलना बताया है।

याचिकाकताओं के दावे के बारे में कानून क्या कहता है? याचिकाकताओं ने मस्जिद स्थल पर अपना दावा स्थापित करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया। दीवानी मुकदमों में, प्रारंभिक दावों को आम तौर पर अंकित मूल्य (प्रथम दृष्टया) पर स्वीकार कर लिया जाता है, अगर मुकदमा विचारणीय माना जाता है तो बाद में और सबूत पेश किए जा सकते हैं। हालाँकि, कोई भी दावा जो पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने की कोशिश करता है, उसे पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत वर्जित किया जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बनाए रखना है जैसा कि वे 15 अगस्त, 1947 को मौजूद थे। पूजा स्थल अधिनियम, 1991 क्या कहता है? अधिनियम पूजा स्थलों के किसी भी रूपांतरण पर रोक लगाता है और यह अनिवार्य करता है कि उनका धार्मिक चरित्र वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह 15 अगस्त, 1947 को था। विशेष रूप से, धारा 3 किसी भी पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य संप्रदाय या संप्रदाय के पूजा स्थल में रूपांतरण पर रोक लगाती है। धारा 4 में कहा गया है कि उस तिथि को किसी स्थान के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन के सम्बंध में कोई भी कानूनी कार्यवाही समाप्त (समाप्त) कर दी जाती है, जिससे ऐसे रूपांतरणों के सम्बंध में नए मुकदमे दायर नहीं किए जा सकते। उल्लेखनीय रूप से, यह अधिनियम अपने अधिनियमन के समय पहले से ही विचाराधीन विवादों पर लागू नहीं होता है, जैसे बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामला, जिसने समकालीन विवादों में इसके आवेदन को जटिल बना दिया है।

न्यायालयों ने इन टाइटल मुकदमों को कैसे अनुमति दी है? पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों के बावजूद, अदालतों ने ज्ञानवापी और मथुरा जैसे स्थानों से सम्बंधित टाइटल मुकदमों को बनाए रखने योग्य करार देकर अनुमति दी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी ने संकेत दिया कि अधिनियम के तहत किसी स्थान की धार्मिक प्रकृति को बदलना प्रतिबंधित है, लेकिन इसके ऐतिहासिक चरित्र की जांच अभी भी अनुमेय हो सकती है। इस व्याख्या ने ज़िला न्यायालयों को अधिनियम की मंशा का सीधे उल्लंघन किए बिना ऐसी याचिकाओं पर विचार करने का आधार प्रदान किया है। संभल के मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित करने से पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया कि क्या दीवानी मुकदमा विचारणीय है। इस एकपक्षीय निर्णय (दोनों पक्षों को सुने बिना) ने इसकी वैधता और निष्पक्षता के बारे में और विवाद पैदा कर दिए हैं। न्यायालयों को 1991 के अधिनियम की मंशा को बनाए रखना चाहिए, यह सुनिश्चित करके कि 15 अगस्त, 1947 तक के स्थलों के धार्मिक चरित्र को चुनौती देने वाले विवादों को खारिज कर दिया जाए, अनावश्यक सर्वेक्षण या कार्यवाही से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को ऐतिहासिक शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से दूर करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने, हिंसक झड़पों के जोखिम को कम करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अंतर-धार्मिक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

भारत में धार्मिक स्थलों पर चल रहे विवाद, विशेष रूप से ऐतिहासिक धर्मांतरण के दावों से जुड़े विवादों ने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है। वाराणसी और मथुरा में इसी तरह के मामलों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं जो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को खतरे में डालने वाले सर्वेक्षणों या कानूनी कार्रवाइयों के रूप में देखे जाने पर सार्वजनिक अशांति में योगदान करते हैं। संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष की दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ी जा रही है, जिसमें अदालत की ओर से आए मस्जिद के सर्वे ऑर्डर पर काम हो रहा है।

पीएनबी ने अपनी एनआरआई सेवाओं को मजबूत किया

मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 23 नवंबर, 2024 को अपने 24-7 एनआरआई ग्राहक सेवा केंद्र के साथ-साथ बैंकिंग सुविधा को बढ़ाने और अपने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने हेतु नई वित्तीय सेवाओं का एक व्यापक सेट लॉन्च किया है। इन पेशकशों का अनावरण बैंक के भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव एम. नागराजू, डीएफएस के संयुक्त सचिव पंकज शर्मा, पीएनबी के एमडी एवं सीईओ अतुल कुमार गोयल, तथा कार्यकारी निदेशकों कल्याण कुमार, बिनोद कुमार, एम. परमशिवम और बिभु प्रसाद महापात्रा की उपस्थिति में किया गया। 7 देशों में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) ग्राहकों के लिए पीएनबी ने विस्तारित टोल-फ्री नंबर, डोरस्टेप डॉक्यूमेंट पिकअप सुविधा, एनआरआई ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग, फॉरवर्ड लिंक्ड प्रीमियम डिपॉजिट स्कीम, 50 विशेष एनआरआई सेवा शाखाएँ, एनआरआई नेविगेटर - ऋ्रद के साथ एक व्यापक गाइड और एनआरआई ग्राहकों की सुविधा के लिए नई वेबसाइट जैसी सेवाएं शुरू की हैं। यह लॉन्च दुनिया भर के ग्राहकों को सुलभ, व्यक्तिगत और निर्बाध बैंकिंग समाधान प्रदान करने हेतु पीएनबी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक के फोकस को मजबूत करता है।

मशहूर लेखक बर्जिस देसाई की क्राइम थ्रिलर किताब मर्डर एट द रेसकोर्स लॉन्च

मुंबई। जाने-माने वकील और प्रसिद्ध लेखक बर्जिस देसाई का नवीनतम उपन्यास मर्डर एट द रेसकोर्स का अनावरण किया गया है। यह उपन्यास आपको हॉर्स रेसिंग की जोखिम भरी दुनिया के गहरे अंधेरे में एक रोमांचक गोता लगाने ले जाता है। अपने नवीनतम उपन्यास की विशेषता के बारे में बोलते हुए, देसाई ने कहा, हॉर्स रेसिंग केवल गति और कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि जुनून, विश्वासघात और लालच से भरी दुनिया है। इस उपन्यास के माध्यम से मैं पाठकों को एक छिपी हुई दुनिया में ले जाता हूं, जहां दांव पर सिर्फ पैसा या ट्रॉफियां नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। मुझे विश्वास है कि किताब आखिरी पन्ने तक पाठकों की सांसें थामे रहेगी। उनकी पिछली रचनाएं जैसे कि ओह! धोस पारसी, द बावाजी और टावर्स ऑफ साइलेंस को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। अब साज़िशों, घोटालों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा साज़िशों का यह नया उपन्यास पहले से ही अपराध और रहस्य प्रशंसकों के बीच हलचल पैदा कर रहा है। इस उपन्यास में रेसकोर्स की पृष्ठभूमि अपने आप में बहुत रोमांचक है क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जहाँ किस्मत सेकंडों में बनती और टूटती है। ऐसी हृदय विदारक पृष्ठभूमि में नारी मनसुखानी नामक कुख्यात प्रशिक्षक की हत्या हो जाती है। इसके बाद घटनाओं का एक जाल है जो हॉर्स रेसिंग की दुनिया को हिलाकर रख देता है। इसके बाद होने वाली जांच में भ्रष्टाचार, डोपिंग और विश्वासघात का एक घातक कॉकटेल उजागर होता है जो भारत के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को भी चकित कर देता है। पुस्तक के पृष्ठ-दर-पृष्ठ मोड़ पाठकों को लगातार बांधे रखते हैं। देसाई स्वयं भी एक पूर्व पत्रकार, रेसिंग स्टीवर्ड और अनुभवी नस्ल ब्रीडर हैं। रेसिंग दुनिया के अपने गहन ज्ञान और अपनी अनूठी शैली के साथ, वह एक रहस्यमय कहानी की दुनिया बुनते हैं जहां रोमांच का स्तर विश्व प्रसिद्ध हिचकॉक-शैली है और साथ ही पूरी तरह से यथार्थवादी भी लगता है।

क्लियर प्रीमियम वाटर ने ह्यटेनिस प्रीमियर लीग सीजन 6 के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा

मुंबई। क्लियर प्रीमियम वाटर एक बार फिर टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) सीजन 6 के लिए पावर-बाय स्पोंसर्स के रूप में आ रहा है, जो खेल प्रतिभा, प्रतिस्पर्धा और टेनिस के प्रति सच्ची भावना का उत्सव है। ये बहुप्रतीक्षित प्रमुख मैच 3 से 8 दिसंबर, 2024 तक मुंबई के प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में खेले जाएंगे। क्लियर प्रीमियम वाटर और टीपीएल के बीच यह दूसरा गठजोड़ है, जो पूरे भारत में प्रमुख खेल के रूप में टेनिस को बढ़ावा देने के उनके साझा दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इस सीजन की यात्रा 25 सितंबर, 2024 को सहारा स्टार, मुंबई में सितारों से सजी खिलाड़ियों की नीलामी के साथ शुरू हुई। एक रोमांचक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने के लिए प्रसिद्ध हस्तियाँ, एथलीट और खेल प्रेमी एकत्र हुए। क्लियर प्रीमियम वाटर के संस्थापक और सीईओ नयन शाह ने इस गठजोड़ के बारे में कहा कि ₹सीजन 6 के लिए टेनिस प्रीमियर लीग के साथ हमारा निरंतर जुड़ाव सिर्फ एक साझेदारी नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा का उत्सव है। क्लियर प्रीमियम वाटर में हम चैंपियन हैं, उत्कृष्टता की खोज में और टेनिस अनुशासन और गतिशीलता के मिश्रण के साथ इस भावना को दशार्ता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मिलकर टेनिस को पसंद के एक महान खेल में बदल रहे हैं साथ ही इसकी पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि करके खेल के प्रति गहरी सराहना को भी बढ़ावा दिया गया। छठा सीजन अविस्मरणीय टेनिस क्षणों का गवाह बनेगा, जिसमें आठ गतिशील टीमें बंगाल विजाड्र्स, बेंगलुरु एसजी पाइपर्स, पंजाब पैट्रियट्स, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, गुजरात पैंथर्स, यश मुंबई ईगल्स, श्री दिल्ली आरएआर टाइगर्स और चेन्नई स्मैशर्स शामिल होंगी... लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, सोनाली बेंद्रे, तापसी पन्नू, रकुल प्रीत सिंह और महेश भूपति जैसे दिग्गज एंबेसेडर इस लीग में स्टार पावर और प्रेरणा लाते हैं।

गोदरेज विक्रोली कुकिना और एफबीएआई ने आईएफबीए 2024 में भारतीय खाद्य संस्कृति के दूरदर्शी लोगों का सम्मान किया

मुंबई/पटना। गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप (जीआईजी) के ब्रांड-अग्नोस्टिक फूड एवं लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म, गोदरेज विक्रोली कुकिना ने फूड ब्लॉगर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफबीएआई) के साथ साझेदारी में सेवन रिवर, ताज हॉलिडे विलेज, गोवा में इंडिया फूड एंड बेवरेज अवार्ड्स 2024 (आईएफबीए) की मेजबानी की। भारत के विविध खाद्य इकोसिस्टम का जश्न मनाते हुए आईएफबीए उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करना जारी रखता है जिनके असाधारण काम ने खाद्य और पाक उद्योग को आकार और पुनर्परिभाषित किया है। प्रमुख सम्मानित लोगों में, शेफ संज्योत कीर को हॉस्पिटालिटी और पाक उद्योग पुरस्कार में प्रतिष्ठित उत्कृष्ट योगदान से सम्मानित किया गया, और कल्याण कर्माकर को एफबीएआई स्टार नामित किया गया। इसके अतिरिक्त, कई अन्य विजेताओं को उनके असाधारण काम के लिए रिकग्नाइज किया गया जिसमें खाद्य समीक्षक पृथ्वीश अशर भी शामिल थे, जिन्हें ईटरी में शीर्ष समीक्षा के लिए इंस्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2024 आईएफबीए ने 11 मुख्य श्रेणियों में प्रतिभा को मान्यता दी, जिसमें 33 उप-श्रेणियां शामिल हैं, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ब्लॉग, यूट्यूब, मीडिया, हॉस्पिटालिटी, सार्वजनिक वोटिंग, एफबीएआई स्टार, उद्योग सहायता, शिक्षा, पीआर एजेंसी और आतिथ्य उद्योग और पाककला में योगदान शामिल हैं। इस वर्ष के समारोह में कुल 155 विजेताओं को सम्मानित किया गया, जो भारत के संपन्न खाद्य और पेय उद्योग के एक रोमांचक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

डॉ. रवींद्र मिश्रा को 'वंदे भारत नेशनल अवार्ड 2024' से किया गया सम्मानित

मुंबई (उत्तरशक्ति)। महाराष्ट्र के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. रवींद्र मिश्रा को 26 नवंबर 2024, संविधान दिवस के अवसर पर, 'वर्थी वेलनेस फाउंडेशन ट्रस्ट' द्वारा 'वंदे भारत नेशनल अवार्ड 2024' से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय उत्कर्ष, और महिला-बाल अधिकारों की रक्षा के प्रति उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया।

'वंदे भारत नेशनल अवार्ड' उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने निस्वार्थ कार्यों और समर्पण से समाज को सशक्त बनाया है। इस साल, डॉ. मिश्रा को यह पुरस्कार उनके असाधारण कार्यों और प्रयासों के लिए दिया गया, जिनकी वजह से असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। डॉ. मिश्रा पिछले कई वर्षों से समाज की सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने वंचित समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में अनेक योजनाएं शुरू कीं। इसके अलावा, उन्होंने महिला और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए। उनकी संगठनात्मक क्षमताओं ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। डॉ. मिश्रा 'राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम् महिला बाल विकास आयोग' के मुख्य महासचिव (महासचिव) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके नेतृत्व में आयोग ने गरीब और जरूरतमंदों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डॉ. मिश्रा के कार्यक्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रही है। उनकी पहल पर कई ग्रामीण इलाकों में महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों का गठन और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। बाल अधिकारों की बात करें तो डॉ. मिश्रा ने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई अनूठे प्रकल्प शुरू किए। उनकी 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मुहिम को देशभर में सराहा गया। उन्होंने बच्चों में पोषण और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया।'राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम् महिला बाल विकास आयोग' के बैनर तले, डॉ. मिश्रा ने सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम किया। आयोग के तहत गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करना, बच्चों के शोषण के खिलाफ आवाज

उठाना, और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना जैसे कार्य शामिल हैं।डॉ. मिश्रा ने आयोग के माध्यम से सैकड़ों मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य किया। उन्होंने बाल श्रम, घरेलू हिंसा, और यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़ितों को कानूनी और मानसिक सहायता उपलब्ध कराई।संविधान दिवस, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, इस वर्ष और भी खास बन गया क्योंकि इस दिन डॉ. मिश्रा को 'वंदे भारत नेशनल अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें न केवल उनके सामाजिक कार्यों के लिए बल्कि उनके नेतृत्व और समाज के प्रति उनके समर्पण के लिए भी दिया गया।पुरस्कार समारोह में 'वर्थी वेलनेस फाउंडेशन ट्रस्ट' की संस्थापक और निदेशक मानसी बाजपेई और प्रशासक हर्षित बाजपेई ने डॉ. मिश्रा को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, ₹डॉ. रवींद्र मिश्रा जैसे समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हमारे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

उनकी सेवाएं समाज में समानता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं ₹डॉ. मिश्रा का जीवन समाज के उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने न केवल वंचितों के लिए काम किया बल्कि समाज के उन युवाओं को भी प्रेरित किया जो सामाजिक सेवा में योगदान देना चाहते हैं।

उनके नेतृत्व में 'राष्ट्रीय मानवाधिकार एवम् महिला बाल विकास आयोग' ने कई नवीन परियोजनाएं शुरू कीं, जैसेः 1. न्याय तक पहुंचः गरीब और जरूरतमंदों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। 2. शिक्षा के क्षेत्र में सुधारः ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए शिक्षण केंद्रों की स्थापना। 3. स्वास्थ्य जागरूकता अभियानः महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर। 4. महिला सशक्तिकरणः कौशल विकास कार्यक्रम और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता।

सुधीर कदम के आकस्मिक निधन से भायंदर में शोक की लहर

भायंदर (उत्तरशक्ति)। मीरा-भायंदर नगरपालिका के पूर्व उप नगराध्यक्ष तथा पूर्व नगरसेवक अरुण बाबाजी कदम के सबसे छोटे भाई सुधीर बाबाजी कदम (उम्र 56वर्ष) का आज सुबह हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया है। अत्यंत विनम्र, शालीन और मिलनसार सुधीर कदम के निधन की खबर मिलते ही भायंदर में शोक की लहर दौड़ गई। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान राहुल एजुकेशन के चेयरमैन लल्लन तिवारी ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि सुधीर कदम के आकस्मिक निधन से हम सबको गहरा आघात लगा है। वे हमारे परिवार के सदस्य की तरह रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा दुःख की इस घड़ी में कदम परिवार को संबल प्रदान करें। वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट आरजे मिश्रा, राहुल

एजुकेशन के सचिव राहुल तिवारी, एड राजकुमार मिश्रा, पत्रकार शिवपूजन पांडे, पत्रकार राजेश उपाध्याय, पत्रकार सुभाष पांडे, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश सिंह, भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे, बृजेश तिवारी, नगरसेवक मनोज रामनारायण दुबे, नगरसेवक मदन उदितनारायण सिंह, प्रवीण राय समेत अनेक लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है।

मोदी जी ने सहकार से समृद्धि के संकल्प के माध्यम से लाखों गाँवों, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला : अमित शाह

मुंबई। हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन-2024 का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया कि, ह्यमोदी जी ने ह्यसहकार से समृद्धिह्न के संकल्प के माध्यम से लाखों गाँवों, करोड़ों महिलाओं और किसानों की समृद्धि का रास्ता खोला।

मोदी जी के नेतृत्व और अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारिता क्षेत्र के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। बीते तीन वर्षों में देश में सहकारिता आंदोलन को ना सिर्फ गति प्रदान की गई है बल्कि जमीनी स्तर पर उसकी

पहुँच को व्यापक बनाने की कवायद भी तेजी से जारी है। यदि देखा जाए तो मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन को और भी अधिक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने का काम अमित शाह की नीतियों और उनके कार्यकाल में हुआ है। कृषि, डेयरी, मत्स्यपालन, बुनाई, ऋण और व्यापार सहित कई प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ सहकारिता क्षेत्र को आजादी के बाद भी वर्षों तक उपेक्षा का शिकार बना कर रखा गया था, जबकि देश की आधी से ज्यादा आबादी किसी-न-किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी हुई है। ऐसे में, सहकारिता क्षेत्र को एक नया क्षितिज प्रदान करने के लिए मोदी सरकार ने जुलाई, 2021 में सहकारिता मंत्रालय के गठन का ऐतिहासिक निर्णय लिया था, जिसका कार्य भार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया। जहाँ मोदी जी ने स्वायत्त सहकारिता मंत्रालय का गठन करके सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने का काम किया, वहीं जन कल्याण से जुड़ी नीतियों के लिए प्रसिद्ध भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में सहकारिता की नींव को मजबूत बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। देश भर के राज्यों में सहकारी समितियों का निर्माण और इसका मजबूत ढाँचा आज इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं।

भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया संविधान अमृत महोत्सव

वसई रोड (उत्तरशक्ति)। भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर मजदूर संघ महाराष्ट्र द्वारा संविधान अमृत महोत्सव का आयोजन उसगआंव में किया गया। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को एक सूत्र में बांधने वाले 'संविधान' दिवस के अवसर पर उपस्थितजनों से बातचीत कर मार्गदर्शन दिया गया, साथ ही देश की आजादी के लिए शहीद हुए और देश की रक्षा करते हुए सीमा पर शहीद हुए वीरजवानों को श्रद्धांजलि देने वाली अखंड ज्योति ₹अमरज्योत₹ को नायक की पत्नी स्मिता सालगांवकर ने प्रज्वलित किया। मुंबई पर 26/11 हमले में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों, जवानों और नागरिकों को श्रद्धांजलि

दी गई. इस अवसर पर श्रमजीव संस्था के नेता विवेक भाऊ पंडित, वसई आमदार स्नेहा दुबे, श्रमजीव संगठन के अध्यक्ष रामभाऊ वार्ना की विधवा स्मिता सालगांवकर, बहादुर सैनिक विजय सालगांवकर, पालघर के कलेक्टर गोविंदराव बोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, वसई विरार मनपा आयुक्त अनिल पवार, वसई तहसीलदार अविनाश कोष्टी, पुलिस आयुक्त जयंत भजाबले, पुलिस आयुक्त पूर्णिमा चौघुले, डीवाईएसपी राहुल जाल्टे, शरद पाटिल एवं श्रमजीवी संगठन के अन्य प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

संगीता पाटील के निरागस काव्य संग्रह का किया गया विमोचन

पालघर(उत्तरशक्ति/अजीत सिंह)। कोकण मराठी साहित्य परिषद बोईसर-तारापुर शाखा की ओर से कवि केशवसुत स्मृति दिवस व काव्य संग्रह प्रकाशन समारोह जिला परिषद विद्यालय चिंचणी क्रमांक-3 तहसील दहानू में संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित संत साहित्य की मर्मज्ञ प्रो. संध्या शाहपुरे के शुभ हाथों संगीता सुधीर पाटील के काव्य संग्रह निरागस-बालकविता" का विमोचन किया गया । इस काव्य संकलन में कविता का बगीचा खूबसूरती से खिल उठा है। आज इस बगीचे में निरागस बालकविता बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक है। वे बहुत आनंद देते हैं। उस काव्य संग्रह से संस्कारयुक्त मन जागृत होता है। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित कोमसाप के जिलाध्यक्ष प्रवीण ना. दवणे ने बोलते हुए कहा कि कविताएं अन्य विषयों पर लिखी जाती हैं, लेकिन बाल कविता लिखना और काव्य संग्रह प्रकाशित करना बहुत ही सराहनीय है। मराठी विषय की शिक्षिका संगीता पाटील ने यह काम करके दिखाया है। शिक्षक

समाज के स्तंभ हैं। शिक्षक पेराल ते उगवेल की भूमिका से पढ़ा रहे हैं।

संगीता पाटील ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ₹नौवीं कक्षा में मेरे स्कूली जीवन के दौरान 1982 में मराठी शिक्षक डॉ. नरेश सावे ने हाथों से लिखी हुई मेरी पहली कविता प्रकाशित की थी। तब से अब तक की कविता की यात्रा, कविताओं का यह संग्रह प्रसिद्ध हो गया साहित्य में रुचि के कारण ही कोमसाप जैसा मुख्य मंच प्राप्त हुआ है। संकलन प्रकाशित करने में मुझे अपने परिवार से बहुत समर्थन और प्रेरणा मिली है। कोमसाप शाखा अध्यक्ष व कार्यक्रम अध्यक्ष प्रो. संजय घरत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इस काव्य संग्रह की कविताएँ उच्च गुणवत्ता की हैं और स्कूल पाठ्यक्रम के लिए चुनी जाएंगी ऐसी आशा व्यक्त की तथा उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों के प्रति आभार जताया। इस समारोह में माधुरी वर्तक, डॉ. नरेश सावे, अनिल सावे, दिनेश तामोरे, सतीश घरत, अंजना सावे, सुजाता पाटील, ज्योति पाटील, सुधीर पाटील, अनिल करवीर, वैशाली शिंदे, विद्या भोरझरे, सुजाता राऊत, साधना सावे, प्रदीप तरे, विनोद वर्तक सहित अनेक गणमान्य लोग प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का परिचय एवं सूत्र संचालन कोमसाप जिला प्रतिनिधि सुहास राऊत द्वारा किया गया।

मानेरा गांव में आग लगने से मकान जलकर राख

महेश गायकवाड़ ने की एक लाख की मदद

कल्याण (उत्तरशक्ति)। कल्याण के मानेरा गांव में आग लगने से एक गरीब किसान परिवार का संसार बर्बाद हो गया। इसकी सूचना मिलते ही महेश गायकवाड ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और गुंजाई फाउंडेशन के माध्यम से एक लाख रुपये की सहायता राशि तत्काल प्रदान की।

जानकारी के मुताबिक बुधवार की सुबह मानेरा गांव के रहने वाले पंढरीनाथ जोशी के मकान में अचानक आग लग गई।

शॉर्टसर्किट के चलते आग लगने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आने से जोशी परिवार का घर जलकर खाक हो चुका है। इस घटना की सूचना मिलते ही महेश

गायकवाड तुरंत ही मानेरा गांव पहुंचे। उन्होंने परिस्थिति का जायजा लिया और जोशी परिवार को एक लाख रुपये की राशि तत्काल मदद स्वरूप दी। साथ ही उन्होंने जोशी परिवार को आगे भी हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस दौरान महेश गायकवाड ने एमएसईबी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बिजली विभाग की लापरवाही से भी यह घटना हो सकती है ।

डॉ आरबी सिंह के कार्यों को याद करते हुए दी गई श्रद्धांजलि

मुंबई (उत्तरशक्ति)। ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी एंड कॉलेज एम्प्लॉईज फेडरेशन- कोलकाता, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ व अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में स्व. डॉ. आर. बी. सिंह सर की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार दि. २६ नवंबर ,२०२४ को बी. के. बिर्ला महाविद्यालय, कल्याण (प) के सभागृह में किया गया. ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी एंड कॉलेज एम्प्लॉईज फेडरेशनके महासचिव नारायण सहा, कोलकाता, तमिलनाडु से के. विजयन, वी. गोपीनाथ, आर. सैयद हुसेन, महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनके संयोजक विश्वास काटकर, आमदार एड निरंजन डावखरे, बि. के. बिर्ला महाविद्यालय के संचालक डॉ. नरेशचंद्र, प्राचार्य फोरमके अध्यक्ष डॉ. टी. ए. शिवारे, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संगठन महासंघ शिक्षण बचाव मंच के डॉ. तपती मुखोपाध्याय, श्रीमती मधु परांजपे, ताहिर मोहमद, के. एम. अग्रवाल महाविद्यालय के डॉ. विजय नारायण

पंडित, मुन्ना पांडे (नमन), अनिल पंडित, बि. के. बिर्ला के प्राचार्य डॉ. अविनाश पाटील, महासंघ के कार्याध्यक्ष शशिकांत कामठे, गोविंद जोशी, महासंघ के उपाध्यक्ष अनिल घाटगे, राजेंद्र गिड्डे, चंद्रकांत धनावडे, महासंघ के चिटणीस डॉ. ऋषिकेश चितम, महासंघ के कोषागार अनिल लबरे, महासंघ के सभी विभागीय पदाधिकारी, अ.म.शि.क. संघके. महासचिव माधव राऊळ, चिटणीस दिलीप पवार, उपाध्यक्ष सुदर्शन आग्रे, चंदर पांडे, सुहास भगत संघके अन्य मान्यवर उपस्थित थे.सभा का सूत्रसंचालन संघ के महासचिव दिलीप मोरे एवम श्री. माधव राऊळ ने किया. सभा समाप्ति के बाद ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटी अॅण्ड कॉलेज एम्प्लॉईज फेडरेशन- कोलकाता, महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ व अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी संघ की संयुक्त बैठक में बहुमत से डॉ. आर. बी. सिंह के असामाईक निधन से रिक्त पद पर डॉ. सुजीत आर. बी. सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासंघके महासचिव तथा अ.म.शि.क. संघके अध्यक्ष पद पर चुना गया।

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति, विश्व समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, मो.- 9554493941 email ID- uttarshaktinews@gmail.com

माँ भराड़ी देवी ने मुझ पर भरपूर कृपा की है: रविन्द्र चव्हाण

आंगणेवाडी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी-महायुति की शानदार जीत से बीजेपी और महायुति के दलों में उत्साह का माहौल है और नेता गण अपने आराध्य भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भाजपा नेता विधायक रवींद्र चव्हाण ने मंगलवार को श्री क्षेत्र आंगणेवाडी में विराजमान श्री देवी भराडी माँ के चरणों में माथा टेका और माँ का आशीर्वाद लिया। सभी कोंकणवासियों की तरह, मेरी भी श्रीक्षेत्र आंगणेवाडी की माँ भराडी देवी के चरणों में आस्था है। मेरी यह आस्था राजनीति के लिए नहीं है, यह भक्ति का मामला है। हमारे लिए सत्ता चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या व्यवसायिक काम हो, हर काम भराड़ी माँ के दर्शन से शुरू होता है। विधानसभा चुनाव के दौरान, मुझे प्रचार अभियान प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसके बाद भाजपा-महायुति के प्रचार प्रमुख के तहत पूरे महाराष्ट्र में महायुति के लिए प्रचार का काम भी माँ भराडी देवी के दर्शन के साथ शुरू किया। पुनः सत्ता में स्थापित होने के लिए माँ के चरणों में प्रार्थना की, मिन्नतें कीं। माँ ने भरपूर आशीर्वाद दिया और माँ की कृपा के फलस्वरूप भाजपा-महायुति को राज्य में ऐतिहासिक जीत हासिल हुई, ऐसा रवींद्र चव्हाण ने कहा। इस अवसर पर भाजपा सिंधुदुर्ग के जिला अध्यक्ष प्रभाकर सावंत, पूर्व विधायक प्रमोद जठार समेत भाजपा-महायुति के कई पदाधिकारी, नेता व कार्यकताओं समेत बड़ी संख्या में कोंकणवासी उपस्थित थे।

संभल में युवकों की मौत और हिंसा के लिए डीएम-एसपी पर हो कार्रवाई

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। लखनऊ रिहाई मंच ने संभल में चार मुस्लिम युवकों की मौत और हिंसा के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मंच ने कहा कि संभल में शांति और सौहार्द के माहौल को बनाए रखने में प्रशासन असफल रहा और उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप है। मृतकों के परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि लड़कों की मौत पुलिस की गोली से हुई है। रिहाई मंच अध्यक्ष मुहम्मद शोएब ने कहा कि संभल मामले में सांसद जियाउर्रहमान पर एफआईआर ने जो कि वहां मौजूद नहीं थे साफ कर दिया है कि यूपी में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। एडवोकेट जफर अली को मीडिया से बात करने के बाद पुलिस ने उठाकर आवाज को दबाने की कोशिश की। आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सम्भल जाने से रोकना या फिर सामाजिक-राजनीतिक लोगों को संभल न आने देना सच को छुपाने की कोशिश है इस मामले में याचिकाकर्ता, सर्वे टीम की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से बहराइच में स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि भाजपा की शह पर साजिश रची गई ठीक इस मामले में भी यही आएगा तीन हजार से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस बताए कि सर्वे टीम के साथ नारा लगाने वालों पर क्या एफआईआर हुई अगर नहीं तो क्यों नहीं। वीडियो फुटेज के आधार पर कार्रवाई की बात करने वाले प्रशासन को बताना चाहिए कि पुलिस द्वारा गोली चलाने और पत्थरबाजी वाले वीडियो पर क्या कार्रवाई की, क्या उन पर भी रासुका लगेगी रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव ने कहा कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद संभल के एसपी जिस तरह से हंस-हंसकर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे वो बेहद शर्मनाक है। इस तरह के असंवेदनशील और गैरजिम्मेदार अधिकारियों का पद पर बने रहना राष्ट्रहित में नहीं है जिस तरह कार्रवाई की बात कर रहे और मीडिया में आ रहा है कि घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ किया ऐसे में फर्जी एफआईआर, गिरफ्तारी और दबिश के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों के आरोपों को देखा जाए तो पुलिस द्वारा यह टारगेट किलिंग का मामला है पुलिस यह कहकर नहीं बच सकती कि उसने गोली नहीं चलाई क्योंकि कई वायरल वीडियो में गोली ही नहीं पत्थरबाजी करती भी पुलिस नजर आई। इससे पहले भी 2 अप्रैल 2018 को दलित समाज द्वारा किए गए भारत बंद, 19-20 दिसंबर 2019 को हुए नागरिकता आंदोलन और किसान आंदोलन के दौरान भाजपा राज में गोलियों से आमजन मारे गए। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका को देखते हुए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने प्राइवेट हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया।सम्भल हो या उपचुनाव, जिस तरह से पुलिस ने महिलाओं तक पर असलहा ताना उससे यूपी पुलिस की मानसिकता को उजागर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि उसने आंसू गैस और लाठियों का प्रयोग किया। गोली चलाने के आदेश के बिना अगर डीएम, एसपी की संभल में मौजूदगी में पुलिस गोलियां चला रही है तो स्पष्ट है कि आला अधिकारियों से उनकी पुलिस ही नहीं संभल रही। अगर ऐसा रहा तो उनपर कार्रवाई होती लेकिन ऐसा बिल्कुल न होना स्पष्ट करता है कि उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है 19 नवंबर 2024 को हुए सर्वे और 24 की सुबह अलग-अलग गलियों से नारेबाजी करते हुए सर्वे टीम के आने के आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठता है वहीं इतने संवेदनशील मुद्दे पर पीस कमेटी,दोनों समुदायों और शहर के संभ्रांत व्यक्तियों को दरकिनार करना कहीं से भी उचित नहीं था।

विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से बनाए रखने हेतु बैठक सम्पन्न

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के सन्दर्भ में बैठक सम्पन्न हुयी बैठक में जनपदों में स्थित विद्युत उत्पादन स्टेशन, पावर सबस्टेशनों, विद्युत वितरण सब स्टेशनों तथा समस्त विद्युत प्रणाली के सुचारू संचालन और सुरक्षा, अति संवेदनशील स्थानों जैसे अस्पतालों, न्यायालय आदि में विद्युत सुचारू विद्युत व्यवस्था बनाए रखने हेतु कार्ययोजना तैयार करने, कर्मचारी संगठनों से समन्वय कर विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के सम्बन्ध में बैठक करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वैकल्पिक उर्जा स्त्रोतों की भी व्यवस्था की जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार हितो का सरकार पूरा संरक्षण कर रही है तथा उनके हित में कार्य कर रही है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) रामअक्षयवर चौहान, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्रनन्दन सिंह, उप जिलाधिकारीगण और विद्युत विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इमामबाड़ा में शव दफन को लेकर शासन प्रशासन ने किया न्याय

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मुफ्तीगंज इमामबाड़ा में शव दफन को लेकर दिनांक 24 नवंबर 2024 को एक समुदाय के लोगों के द्वारा जबरदस्ती मुफ्तीगंज इमामबाड़ा में शव दफन को लेकर अड़े रहे। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा समस्त कागजात को देखते हुए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ में रजिस्टर्ड वक्फ संपत्ति इमामबाड़ा मुफ्तीगंज के नाम नंबर 1723 इंद्राज है। जिसका खसरा खतौनी में आराजी नंबर 489 व 490 इमामबाड़ा या रास्ते के नाम से दर्ज है। 24 नवंबर 2024 को इमामबाड़ा के बगल के रहने वाले इम्तियाज व उनके परिवार के लोगों के द्वारा इमामबाड़े की जमीन पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 24 नवंबर 2024 दिन इतवार को नाखुदा पुत्र अब्दुल रऊफ की मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त लोग जमीन पर कब्जा करने के नियत से शव दफन करने के लिए कब्र खोदने लगे। जिस पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मुतवल्ली डॉ.बादशाह रिजवी द्वारा आपत्ति की गई। जिसको शासन प्रशासन के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया और एक सूचना पर केराकत क्षेत्राधिकारी , केराकत प्रभारी निरीक्षक,चौकी प्रभारी युगल किशोर राय, के साथ उप जिलाधिकारी केराकत सुनील कुमार,एवम मौके पर सभी अधिकारी पहुंचे गए और लॉयन ऑर्डर को मेंटेन करते हुए दोनों पक्षों को सुनने और पूर्व में लिखे स्टाम्प पर सुलहनामा देखा और कागजात का अवलोकन किया। जिसपर उप जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि उक्त संपत्ति इमामबाड़ा की है जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है इस पर विपक्ष पक्ष के द्वारा पूर्व में स्टांप पेपर पर लिखित सुलहनामा दिया गया था कि आज के बाद हमारे परिवार से किसी भी व्यक्ति को दफन नहीं किया जाएगा। सुलह नामा में बाद भी जबरन इमामबाड़ा मुफ्तीगंज में शव को दफन करना चाहते थे लेकिन पुलिस विभाग के आलाधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यहां कोई भी शव दफन नहीं किया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन रात्रि 9:00 बजे मृतक नखरू को मुफ्तीगंज के सुन्नी कब्रिस्तान में दफन किया गया और मुतवल्ली को निर्देशित किया कि पूर्व में लिखे गये सुलह नामा के हिसाब से इमामबाड़ा मुफ्तीगंज की वक्फ संपत्ति को बाउंड्री वाल करा लें। जिससे भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न होने पाए।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल द्वारा चाइनीज मांझा के खिलाफ सौंपा ज्ञापन

-अभिलाश गुप्ता

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जौनपुर द्वारा घातक और जानलेवा चाइनीज मांझा की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल का एक प्रतिनिधिमण्डल जिलाध्यक्ष विवेक सिंह के नेतृत्व में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की बिक्री को पूर्णतया प्रतिबंधित करने के लिये जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह से मिलकर उनको एक पत्रक दिया। इस मौके पर संगठन के मुखिया विवेक सिंह ने कहा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइनीज मांझा पूरे देश में प्रतिबंधित है लेकिन यह जौनपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेचा जा रहा है और जानलेवा चाइनीज मांझा से आये दिन जनपद वासी रास्ते में आते-जाते भयानक रूप से घायल हो जा रहे हैं। किसी की गर्दन कट जा रही है किसी की नाक कट जा रही है अभी बीते रविवार को ही रमेश मौर्य नामक व्यवसायी की चाइनीज मांझा से गर्दन कटी है इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है अभी कुछ दिन पूर्व नगर मजिस्ट्रेट को एक पत्रक दिया गया था और इस तरह का अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुरोध किया गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने यह संकल्प लिया कि अब न चाइनीज मांझा बचेंगे और न ही बिकने देंगे लेकिन कुछ दिनों से कुछ लोग बनारस, कानपुर जैसे शहरों से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा लाकर चोरी–छिपे बेच रहे हैं।अब आने वाले महीना में पतंग का सीजन शुरू हो रहा है। मकर संक्रांति इसका प्रमुख त्योहार होता है। इस दौरान तमाम लोग लालच में आकर इसको बेचने का काम करेंगे। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल आप से यह मांग करता है कि आम जनमानस की जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये घातक और जानलेवा चाइनीज मांझा की बिक्री को पूरे जनपद में प्रतिबंधित करने का कष्ट करें जिससे पूरे जनपद में अप्रिय प्राणघातक दुर्घटना पर विराम लग सके। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने विषय की गंभीरता को समझते हुए अपने मातहत अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें, जो भी लोग इस तरह का अवैध कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कानूनी कार्यवाही की करें जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने व्यापार मंडल के लोगों को आश्वासत किया कि आप समाज हित में अच्छा कार्य कर रहे हैं जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह, नगर युवा इकाई के अध्यक्ष अमित जायसवाल, महामंत्री योगेश साहू, निर्भय चन्द्र केडिया,गुलाब पतंग वाले, मोना भाई उपस्थित रहे।

मामूली विवाद में कार चढ़ा कर युवक को उतारा मौत के घाट, दबंगों पर लगाया आरोप

इम्तियाज अहमद

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। जलालपुर थाना क्षेत्र के मकरा चौराहे पर मामूली विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने एक 24 वर्षीय युवक पर गाड़ी चढ़ाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप यह भी है कि दबंगों द्वारा कार को कई बार आगे पीछे करके युवक के ऊपर चढ़ाई गई। घटना के बाद परिजन घायल युवक को वाराणसी के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले गयें। जहां डाक्टरों ने युवक को मृत्यु घोषित कर दिया। युवक के मृत्यु के बाद परिजन शव घर लाकर हंगामा करनें लगें। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन शव सड़क पर रखकर चक्का जाम करने की कोशिश कर रहें थे। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी एसपी सिटी, सीओ, सहित कई थाने की पुलिस पहुंच गई। मौके पर केराकत के सपा विधायक तुफानी सरोज भी पहुंच गये और उग्र भीड़ को किसी तरह समझा बुझा कर शांत कराया। जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में ले पाई। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के मकरा चौराहे के पास की है। बताया गया कि रेहटी गांव निवासी पंकज राजभर का उसी गांव के छोटू सिंह, रोहित सिंह से कुछ बातों को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहा सुनी के बाद विवाद मारपीट में बदल गई। आरोप है कि मारपीट से गुस्साए छोटू सिंह और रोहित सिंह अपने कार को पंकज के ऊपर चढ़ा दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के गिरफ्तार के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

अधिवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी

अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व सीओ दिया ज्ञापन

मछलीशहर, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर के चौलहा(चौरहा)मोहल्ले के निवासी तहसील अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार मौर्य को जान से मारने की धमकी मिलने से साथी अधिवक्ता आक्रोशित हो गए। अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ एवं क्षेत्राधिकारी गिरेंद्र सिंह को ज्ञापन देकर आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग किया। कस्बा घिसुआ खास की जमीन की पत्थरगड्डी के मामले में मुकदमें में पैरवी करने वाले भुक्तभोगी अधिवक्ता का आरोप है कि मेरे विरुद्ध कोतवाली में विरोधियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 ए,351(3),126(2)के अंतर्गत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। अभी उसकी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि मंगलवार की रात 9:25 बजे और 12:03बजे दो नंबरों से फोन कर धमकी दी गई कि मैं लखनऊ सपा कार्यालय से बोल रहा हूं। अमुक मुकदमें पैरवी करना छोड़ दो और रोड़ा मत बनो नहीं तो वकालत का लाइसेंस निरस्त करा दूंगा और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अधिवक्ता ने अपनी व परिवार की सुरक्षा सहित आरोपी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की मांग किया।क्षेत्राधिकारी ने कोतवाल मछलीशहर को फर्जी मुकदमें से अधिवक्ता का जांचकर नाम निकालने एवं आरोपी की विरुद्ध कार्यवाही का निर्देश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, आर पी सिंह,राज कुमार पटवा,आलोक विश्वकर्मा,हरि शंकर यादव,अमित सिंह,रमेश चंद्र यादव,अनुराग श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे।

पहली बार 14 विभागों में होगा क्वालिटी कंट्रोल सेल

वाराणसी(उत्तरशक्ति)। बीएचयू के हर विभाग के पास अब अपना क्वालिटी कंट्रोल सेल होगा। इसे विभागीय गुणवत्ता प्रकोष्ठ या डीक्यूसी कहा जाएगा। अभी तक यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही यूनिट होती थी। पहली बार बीएचयू ने इसे विभागीय स्तर पर खोलने का फैसला लिया गया है। हर विभाग में रिसर्च और एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने पर काम होगा। विभागों में वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों के रिसर्च और पेटेंट का हिसाब-किताब होगा। विभाग की जरूरतों पर भी काम करेंगे। इस सेल में तीन सदस्य होंगे।जो कि विभाग के ही प्रोफेसर, दूसरे एसोसिएट प्रोफेसर और तीसरे असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। विज्ञान संस्थान के विभागों में डीक्यूसी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 नवंबर को विज्ञान संस्थान के निदेशक कार्यालय से सभी 14 विभागों को अति आवश्यक लेटर जारी किया गया है। निर्देश दिया गया है कि बीएचयू के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के कोऑर्डिनेटर के अनुरोध पर विभागों में सेल का गठन किया जाए। विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग में डीक्यूसी बनाएं। इसकी रिपोर्ट भेजें, ताकि बीएचयू के आईक्यूएसी को भेजा जा सके। प्रोजेक्ट की मिलेगी डिटेल रिसर्च और पेटेंट का डेटा विभागों में बनकर तैयार होगा।हर एक प्रोफेसर और वैज्ञानिकों के रिसर्च को बढ़ावा देने पर काम होगा। रिसर्च और पेटेंट के बाद कितने वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को प्रोजेक्ट मिला है।उसकी पूरी डिटेल होगी। उसमें आवंटित फंड और अवधि भी होगी। विभागीय उपलब्धियों को सहेज कर रखा जाएगा। इसे उच्चाधिकारियों और संस्थान को अवगत कराया जाएगा।

पुलिस ने चोरी करने वाले दो को किया गिरफ्तार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। डा0 अजय पाल शर्मा द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के दिशा निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना लाइनबाजार पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 निखिलेश तिवारी, उ0नि हरिशंकर यादव मय हमराह का0 कैलाश यादव, का0 रूस्तम कुमार थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर द्वारा चेंकिग के दौरान मुखबीर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 588/24 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. व मु0अ0स0- 617/24 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस के रैकी कर भैस / बकरी चोरी करने वाले दो व्यक्ति कलीचाबाद सकरी पुलिया लखनऊ रोड के पास से आ रहे है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास कर कलीचाबाद सकरी पुलिया लखनऊ रोड के पास से रैकी कर भैस / बकरी चोरी करने वाले अभियुक्तगण एहतेशाम पुत्र अजिउल्ला निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली जनपद जौनपुर, मो० परवेज उर्फ सिब्बू पुत्र इसरार आलम निवासी पुरानी बाजार थाना कोतवाली जनपद जौनपुर को 27 नवंबर 2024 को समय 12.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभि0- एहतेशाम उपरोक्त के जामा तलासी से भैस / बकरी चोरी से मिले हिस्से के 1500 रूपया व अभि0- मो0 परवेज उर्फ सिब्बू उपरोक्त के जामा तलासी से से भैस / बकरी चोरी से मिले हिस्से के 6500 रूपया के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया ।

ट्रांसफार्मर पर चढ़ा प्राइवेट लाइनमैन, बुरी तरह झुलसा

धर्मेंद्र कुमार शर्मा

बदलापुर,जौनपुर (उत्तरशक्ति)। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरा मुकुंद में बुधवार की शाम को एक प्राइवेट लाइनमैन अजय हरिजन ट्रांसफार्मर पर चढ़कर कोई कार्य कर रहे थे।

जिसके दौरान अचानक 11 हजार बोल्ट विद्युत करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए। आसपास के लोगों के द्वारा जिन्हें आनन फानन में उपचार हेतु बदलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां पर चिकित्सक ने लाइनमैन की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। ज़िला अस्पताल के डॉक्टरों ने देखने के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज दिया है हालत नाजुक देखते हुए ।वहीं लोगों के अनुसार बताया जा रहा है कि मंटू कारलो कंपनी में प्राइवेट लाइनमैन के रूप में कार्यरत है।

फिल्मफेयर ओटीटी अवाड्र्स 2024 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा की

मुंबई (उत्तरशक्ति)। फिल्मफेयर ने मुंबई के टाइम्स टॉवर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेन्यूब प्रॉपर्टीज फिल्मफेयर ओटीटी अवाड्र्स 2024 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा की। इस आयोजन के सह-प्रायोजक हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। फिल्मफेयर ओटीटी अवाड्र्स में ओटीटी इंडस्ट्री में शानदार काम करने वाले कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा, कहानी कहने के शानदार अंदाज के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे और एक्टिंग, डायरेक्शन से लेकर टेक्निकल इंडस्ट्री के लोगों को भी उनके बेहतरीन काम के लिए अवाड्र्स से नवाजा जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटरटेन्मेंट इंडस्ट्री की दिग्गज हस्तियां भूमि पेडनेकर, प्रसिद्ध फिल्म निमार्ता जोड़ी राज निदिमोरु और कृष्णा डी.के. के साथ-साथ फिल्मफेयर के प्रधान संपादक जितेश पिल्लई भी मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न कैटगरी में नॉमिनेट होने वाले कलाकारों की घोषणा की गई, जिनमें गन्स एंड गुलाब्स, हीरामंडीः द डायमंड बाजार, काला पानी, कोटा फैक्ट्री, मेड इन हेवन सीजन-2, मुंबई डायरीज सीजन-2 और द रेलवेमैन को सर्वश्रेष्ठ सीरीज के लिए नॉमिनेट किया गया। अमर सिंह चमकीला, भक्षक, जाने जां (करीना कपूर अभिनीत), ह्यकड़क सिंह, अनन्या पांडे अभिनीत खो गए हम कहां, और मस्त में रहने का को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। अर्जुन माथुर (मेड इन हेवन सीजन-2), गगन देव रियार (स्कैम 2003ः द तेलगी स्टोरी), केके मेनन (बंबई मेरी जान), प्रियांशु पैनयुली (शहर लखोट), रितेश देशमुख (पिल), और सूर्य शर्मा (अनदेखी सीजन-3) को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (मेल) सीरीज ड्रामा के लिए नॉमिनेट किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (फीमेल) सीरीज कॉमेडी के लिए गीतांजलि कुलकर्णी (गुल्लक-4), मानवी गगरू (हाफ लव हाफ अरेंज्ड), नीना गुप्ता (पंचायत सीजन-3), रसिका दुग्गल (ह्यूमरसली योर्स सीजन-3) और तिलोत्तमा शोम (त्रिभुवनदास मिश्रा सीए टॉपर) को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए नॉमिनेट किया गया। इस आयोजन के बारे में अपने विचार रखते हुए भूमि पेड़नेकर ने कहा, बतौर एक्टर मेरे सफर में ओटीटी प्लैटफॉर्म का बहुत अहम योगदान रहा है। पिछले साल ही मुझे इस मीडियम पर एक्टिंग दिखाने का मौका मिला और इससे मेरा यह यकीन और भी पुख्ता हुआ कि अच्छे कॉन्टेन्ट का कोई मुकाबला नहीं है।

शाहगंज में 8.34 करोड़ की लागत से बनेंगे दो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय

विधायक रमेश सिंह ने भूमि पूजन कर किया शिलान्यास

शाहगंज,जौनपुर(उत्तरशक्ति)।शाहगंज तहसील क्षेत्र में आठ करोड़ चौंतीस लाख की लागत से दो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण होगा। बुधवार को शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने दोनों विद्यालयों का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। श्री सिंह ने इस दौरान दोनों स्थानों पर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की विशेष कृपा से शाहगंज का विकास गति पकड़ चुका है। जनपद में एकमात्र शाहगंज ही ऐसी विधानसभा है जहां पर 8.34 करोड़ की लागत से खुटहन के ग्राम सभा तिसौली स्थित प्राथमिक विद्यालय, आर्यनगर में यथा शाहगंज (सोंधी) के प्राथमिक विद्यालय, बड़ौना में एक-एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें समाज के गरीब तबके की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही आवास व भोजन की व्यवस्था मिलेगी। इस दौरान उन्होंने शाहगंज में कराए जा रहे अन्य विकास कार्यो की भी चर्चा की। कार्यक्रम में खुशीराम मिश्र, प्रधान ओम प्रकाश यादव, सुरेंद्र निषाद, पंचम बिंद, सुधीर सिंह बब्बू, वंश बहादुर पाल, अशोक बिंद, अजय सिंह राजू, रविकांत विश्वकर्मा, प्रधान कृष्ण चंद गौतम, कस्तूरबा वार्डेन शाहगंज एकता नीलम, किरण मौर्या व पूजा सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

नगदी समेत 50 लाख रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ

फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस चोरों तक पहुंचने का कर रही है प्रयास

-रियाजुल हक

जौनपुर(उत्तरशक्ति)। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के सिद्दीकपुर गांव में मंगलवार की देर शाम चोरों ने सुनसान घर को निशाना बनाते हुए करीब 52 लाख रुपये मूल्य का सामान चोरी कर लिया। चोरी गए सामान में 700 ग्राम सोने और 700 ग्राम चांदी के आभूषणों के साथ एक लाख नकद शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सिद्दीकपुर निवासी दुष्यंत सिंह मंगलवार शाम को अपने मित्र से मिलने रोड स्थित पेट्रोल पंप गए थे। उनकी पत्नी रेनू सिंह, बड़े बेटे के साथ खुद को डॉक्टर को दिखाने पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित स्किन रोग विशेषज्ञ के पास गई थीं। घर में ताला बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने 7:00 से 9:45 के बीच घटना को अंजाम दिया।चोरों ने पहले मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ा और फिर बेडरूम का और उसमें रखी अलमारी का ताला तोड़कर लॉकर में रखे सोने और चांदी के आभूषणों के साथ नकद चुरा लिया। चोरी गए आभूषणों में सोने की चेन, मंगलसूत्र, अंगूठी, कंगन, नथिया, झाला आदि और चांदी के गहने शामिल हैं।गांव के लोगों का मानना है कि चोरों को पहले से यह जानकारी थी कि घर में कोई मौजूद नहीं है। घर की गतिविधियों पर नजर रखते हुए उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त परिवार का हर सदस्य घर से बाहर था। जिससे चोरों को आराम से काम करने का मौका मिल गया।दुष्यंत सिंह के अनुसार, चोरी गए सामान का अनुमानित मूल्य 52 लाख रुपये है। इसमें 700 ग्राम सोने के आभूषण, 700 ग्राम चांदी और ?1 लाख नकद शामिल हैं। इस घटना ने गांव में दहशत फैला दी है, और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।सूचना मिलने के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फिंगरप्रिंट लिए गए और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

जय मां विंध्यवासिनी सेवा संस्था द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन

प्रेम चंद मिश्रा

नालासोपारा (उत्तरशक्ति)। नालासोपारा पूर्व प्रगतिनगर में जय मां विंध्यवासिनी सेवा संस्था द्वारा आयोजित श्री मद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन मंगलवार भव्य कलशयात्रा के साथ श्री गणेश हुआ। समय सायं 4 बजे 8 बजे रात्रि तक चलने वाले सप्त दिवसीय भागवत महापुराण के कथा व्यास भागवताचार्य पू. कुणाल जी महराज है, तो आचार्य के रूप में पं.शशिकांत मिश्रा पं. संतोष तिवारी पं.अशोक पांडे के सानिध्य में 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक बहने वाली भागवती गंगा के प्रवाह का विश्राम 3 दिसंबर महाप्रसाद के साथ समस्त जन श्रोताओं की उपस्थिति में होगा। जगतकल्याण की भावना से लोकहितार्थ भागवत कथा के आयोजन में आयोजन समिति ने सभी धर्मावलंबियों से अपील किया है कि इस कथा में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य करें। बता दें कि धर्मसार नगरी नालासोपारा में भागवत कथाओं का आयोजन अनेकों संस्थाओं द्वारा निरंतर होते रहते हैं। इसलिए इसे लोग धर्मनगरी के रूप में भी जानते हैं। मंगलवार सुबह से ही कलशयात्रा को सफल बनाने में विशेषतः महिलाओं का विशेष सहयोग दिखाई दिया जिसमें पुरुष व बच्चों की संख्या भी सराहनीय रही।

कलशयात्रा के अवसर पर कथा आयोजन समिति सभी सदस्यों अध्यक्ष राजेश तिवारी, कार्याध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला , नरेंद्र दूबे सोनू, विनोद पांडे, वशिष्ठ तिवारी,दीपक दूबे, बृजेश तिवारी,अभय मिश्रा,उमाकांत पांडे बच्चा गुरू ,अनिल पाठक, इतेश मिश्रा,सुलेष शुक्ला, धर्मेंद्र मिश्रा, विनोद दूबे, संतोष दूबे, अरविंद दूबे,पंकज तिवारी,राजेश मिश्रा, गोविंद पांडे,वेदमणी पांडे,विरामन पांडे 'अमन' , अनिकेत पांडे सहित तमाम भक्तगण उपस्थित रहे! यह जानकारी दैनिक उत्तर शक्ति समाचार पत्र के पत्रकार आनंद कुमार मिश्रा ने दी है।

बाइक डिवाइडर से टकराई, व्यक्ति की मौत

- प्रियेश गुप्ता रुद्र

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। थाना गौराबादशाहपुर क्षेत्र के इटावोली मोड के पास मंगलवार की देर रात 7:30 बजे लगभग बाइक सवार मोहन चौहान 45 वर्ष पुत्र श्याम देव चौहान निवासी आजमगढ़ मेहनगर सोमवार को जौनपुर रिश्तेदार के लिए आए हुए थे ल। मंगलवार को घर आजमगढ़ मेहनगर के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में इटावोली मोड के पास बाइक डिवाइडर में जा टकराई आसपास के दुकानदारों ने देखा तो डायल पर कॉल कर सूचना दिया। सूचना मिलते डायल 112 मौके पर पहुंचकर उपचार के लिए गौराबादशाहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य ले जया गया चिकित्सक ने देखने के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया । ज़िला अस्पताल के डाक्टरो ने देखने के बाद मृत्यु घोषित कर दिया। जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को लगी सभी अचंभे में आ गया। उसी समय रोते बिलखते हुए ज़िला अस्पताल जौनपुर की तरह निकल लिए।शव को मरुचरी हाउस में रखा दिया गया है पोस्टमार्टम बुधवार को होगा बाकी की पुलिस विधि करवाई में जुटी हुई है ।

ट्रैक्टर रेलिंग तोड़ फुटपाथ पर चढ़ा, बड़ी दुर्घटना टली

डॉ.एस.के.मिश्र

वाराणसी(उत्तरशक्ति)। वाराणसी के तेलियाबाग तिराहे पर देर रात तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया। घटना में संजोग रहा कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह हादसा पटेल धर्मशाला के पास हुआ, जहां ट्रैक्टर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सीधे रेलिंग को तोड़ते हुए फुटपाथ पर जा पहुंचा। रफ्तार और नियमों की अनदेखी बनी बड़ी समस्या रात होते ही शहर की सड़कों पर ट्रैक्टरों का बेखौफ संचालन जारी रहता है। ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं।मानो सड़क पर उनके अलावा कोई और मौजूद ही न हो। यातायात माह के दौरान भी इस प्रकार की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। हैरानी की बात यह है कि शहर में चलने वाले 90% ट्रैक्टरों पर

नंबर प्लेट नहीं होते। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि अधिकांश ट्रैक्टर चोरी के या अवैध हो सकते हैं। बिना लाइसेंस मजदूर चला रहे ट्रैक्टर शहर में बड़ी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर भी देखे गए हैं। जिनके चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इनमें से कई चालक पेशेवर ड्राइवर भी नहीं हैं।बल्कि खनन कार्यों में लगे मजदूर हैं। ऐसे में सड़क पर ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार से बढ़ती घटनाओं के लिए प्रशासन की उदासीनता जिम्मेदार मानी जा रही है। शहर में हो रहे अवैध निर्माण और प्रशासनिक उदासीनता बनी समस्या निर्माण कार्यों में लगे इन ट्रैक्टरों को सड़कों पर अवैध तरीके से चलने की छूट मिल रही है। कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर बेहिसाब तरीके से शहर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं।लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। पैसों की खनक ने पुलिस की आंखों पर बांध रखी है पट्टी आए दिन हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद पुलिस कमिश्नरेट इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है। थानों के प्रभारी इन ट्रैक्टरों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इस प्रकार के ट्रैक्टर यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का मौन रवैया जनता की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। आये दिन ट्रैक्टर से हो रहे दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है।